चित्रकथा

ऑरिजित सेन और समर्थ

हिन्दी अनुवाद: सलिल चतुर्वेदी

20 का गिरोह

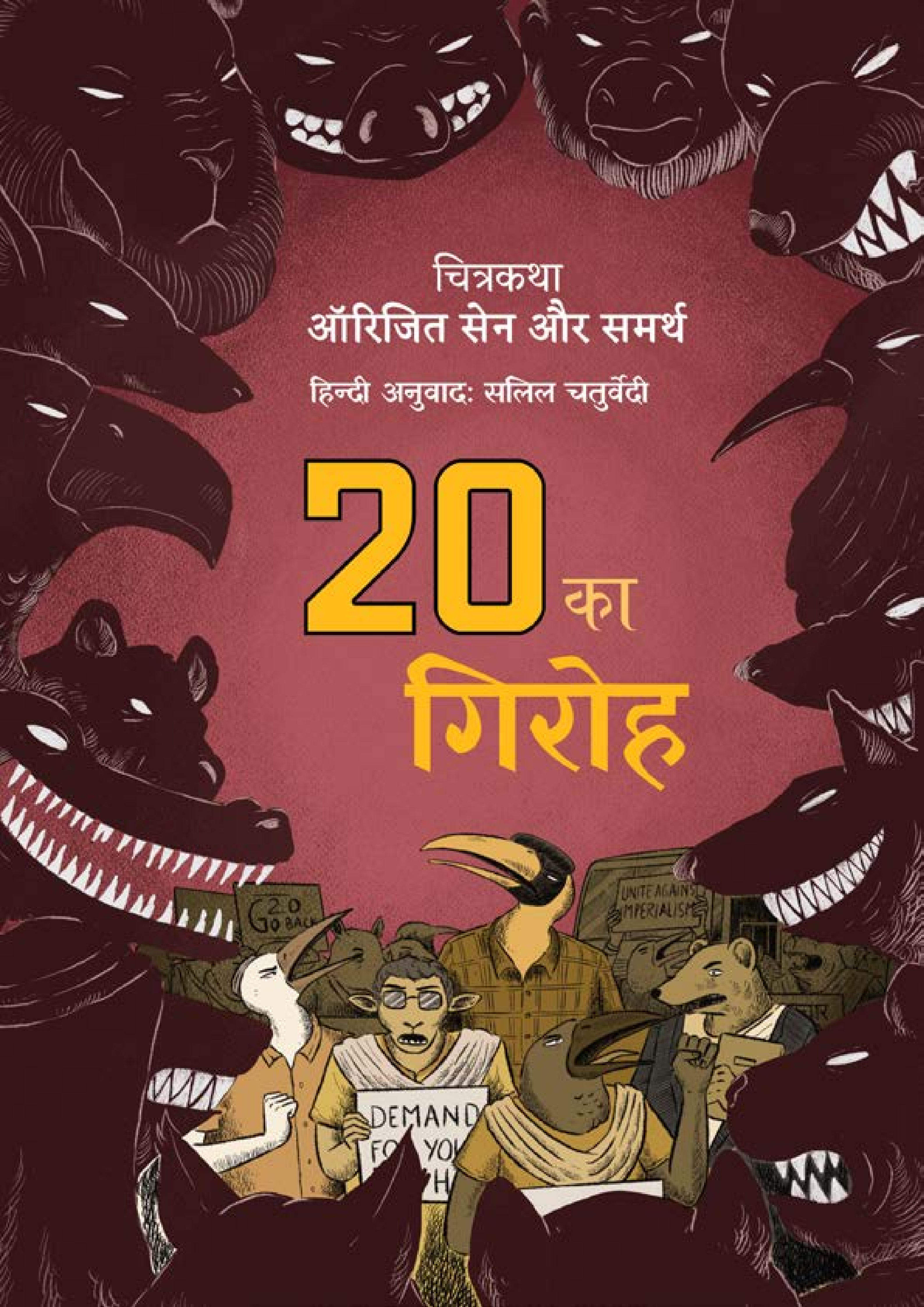

सेंटर फॉर फैनैनशीयल अकाउंटेबिलिटी (CFA) वित्तीय संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में संलग्न है और ऐसे प्रयासों का समर्थन करता है। हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के निवेश पर नज़र रखते हैं, और ऐसी नीतियों पर काम करते हैं जो देश के बैंकिंग क्षेत्र और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। हम इसे अनुसंधान, अभियानों और प्रशिक्षण के माध्यम से करते हैं और साथ-साथ उन आंदोलनों, संगठनों, कार्यकर्ताओं, छात्रों और युवाओं की मदद करते हैं जो अभियानों के द्वारा नीतियों में बदलाव लाना चाहते हैं और सार्वजनिक प्रवचन को बदलने की कोशिश में लगे हैं जिससे नागरिकों को बैंक और वित्त की दुनिया समझने में आसानी हो और बैंक व सरकारें अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनें।

ओरिजीत सेन एक ग्राफिक कलाकार, म्यूरलिस्ट, कार्टूनिस्ट और डिज़ाइनर हैं, और गोवा, भारत, में निवास करते हैं। वह People Tree के सह-संस्थापक हैं, जो कलाकारों, डिज़ाइनरों और शिल्पकारों के लिए एक सहयोगी स्टूडियो एवं स्टोर है। ओरिजीत River of Stories (1994) के लेखक हैं, जिसे भारत का पहला ग्राफिक उपन्यास माना जाता है। 2021 में ओरिजित ने एकतारा ट्रस्ट के सहयोग से युवा पाठकों के लिए Comixense—एक त्रैमासिक कॉमिक्स—लॉन्च किया, और वे इसके मुख्य संपादक हैं। वह कॉमिक्स और ग्राफिक कला पढ़ाते भी हैं, और गोवा विश्वविद्यालय में 'मारियो मिरांडा चेयर विजिटिंग प्रोफेसर' के साथ-साथ अशोक विश्वविद्यालय के विजुअल आर्ट्स विभाग में विजिटिंग प्रोफेसर भी रह चुके हैं।

समर्थ एक ग्राफिक उपन्यासकार और शोधकर्ता हैं। उनका पहला ग्राफिक उपन्यास, Suit, जनवरी 2022 में योडा प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया। उनका काम उनके लिए सामाजिक-राजनीतिक संबंधों का अध्ययन और व्याख्या करने का एक साधन रहा है। पिछले दो वर्षों से वे सामाजिक और विकास क्षेत्र में भी कार्यरत रहे हैं, जिसके द्वारा वे माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए सीखने के नवीन अनुभवों का निर्माण कर रहे हैं। उनका अधिकांश स्वतंत्र कार्य कार्य-घंटों से पहले और बाद में होता है। आप इन्हें इंस्टाग्राम पर roeqin हैंडल के तहत पा सकते हैं।

सोनल रघुवंशी पुस्तक की संपादक और समन्वयक हैं तथा इस पुस्तक के अंत में प्रकाशित सूचना पृष्ठों की लेखिका हैं। वह एक राजनीतिक अर्थव्यवस्था शोधकर्ता हैं और वर्तमान में सेंटर फॉर फाइनैन्शल अकाउंटेबिलिटी से जुड़ी हुई हैं। उनका शोध आर्थिक अनुशासन के साथ-साथ विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में विकास में वित्त की भूमिका (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ गंभीर रूप से संलग्न) और व्यापक आर्थिक नीति को देखता है। सोनल एक अकादमिक पत्रिका की सहयोगी संपादक हैं और विभिन्न प्रगतिशील छात्र समूहों और आंदोलनों के साथ एक आयोजक भी हैं।

Printed by Jerry Printers

Published by:
Centre for Financial Accountability
R21, South Extension Part 2
New Delhi 110049, India
www.cenfa.org
email: info@cenfa.org

This publication was published with the support of Heinrich Böll Stiftung. The views and expressions contained herein are the those of the authors and partners, and do not neccessarily represent the views of Heinrich Böll Stiftung.

This comic is a work of fiction and any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. The book attempts to demystify seemingly complex political economy issues beyond the regular formats.

HEINRICH BÖLL STIFTUNG
REGIONAL OFFICE NEW DELHI

This work is licensed under Creative Commons License CC BY-NC-ND
This license allows reusers to copy and distribute the material in any medium or format in unadapted form only, for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator.

CC BY-NC-ND includes the following elements:
BY – Credit must be given to the creator
NC – Only noncommercial uses of the work are permitted
ND – No derivatives or adaptations of the work are permitted

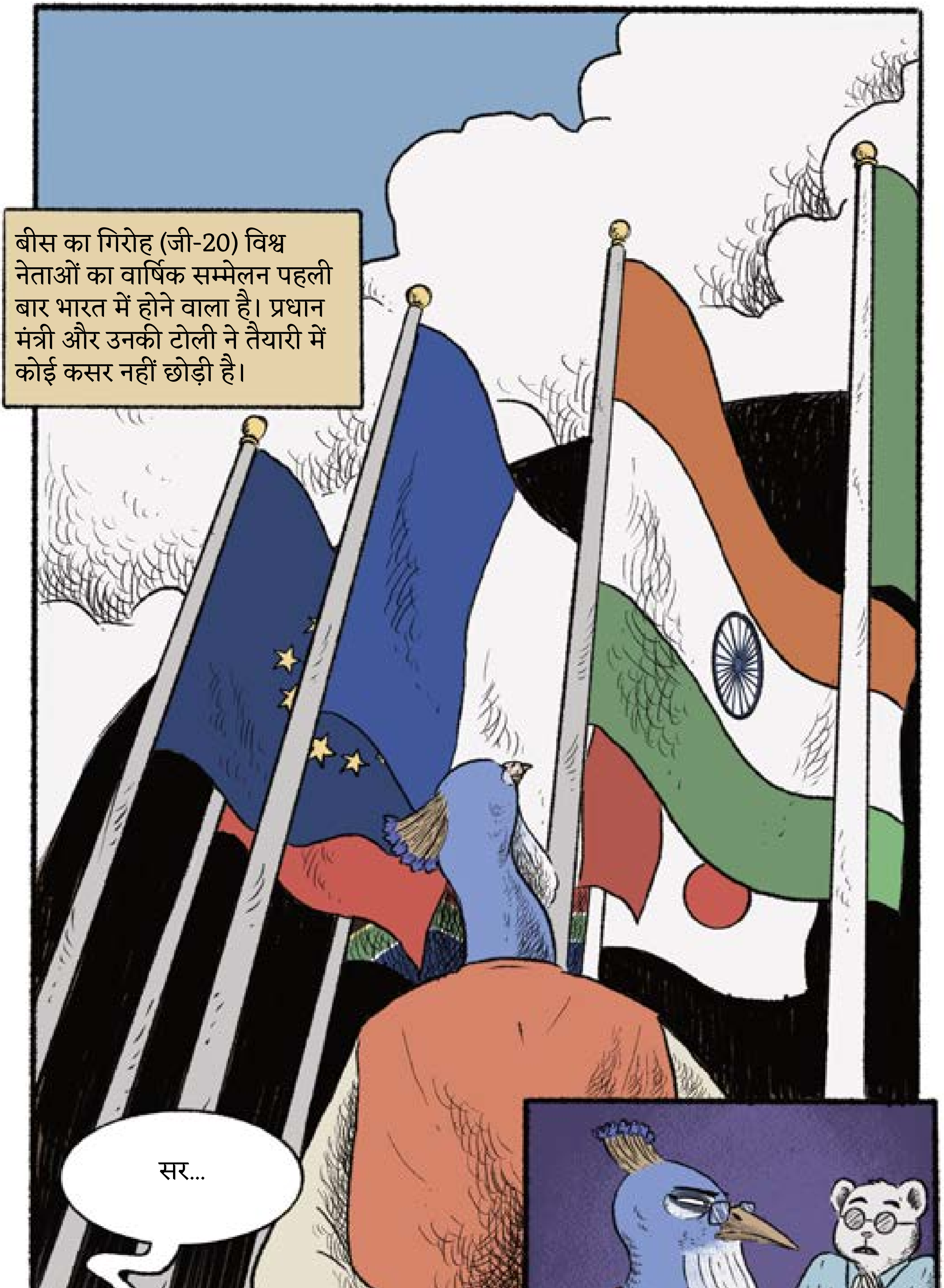
बीस का गिरोह (जी-20) विश्व नेताओं का वार्षिक सम्मेलन पहली बार भारत में होने वाला है। प्रधान मंत्री और उनकी टोली ने तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
सर...

बोलो, क्या है?
सर, सभी वर्कस्टेशनों के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल को रूट कर दिया गया है। संचार के लिए 300 से अधिक फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाए गए हैं।
बहुत बढ़िया! देखो, सब कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए। जो उन कनाडा वालों ने पिछले जी-20 सम्मेलन में किया था, उस से दो कदम आगे।
सम्मेलन स्थल का निर्माण 'चाय-पानी' झील के तट पर रिकार्ड समय में किया गया है। झील का पुनः नामकरण भी प्रधान मंत्री ने उन दिनों की याद में किया है जब वे एक नज़दीकी टूरिस्ट स्पॉट पर चाय बेचा करते थे।
जैसे-जैसे जी-20 के नेतागण पधारते हैं वे तैयारियों से बहुत प्रभावित होते हैं।
वाह! हमें ऐसी भव्यता की उम्मीद नहीं थी!
कोरिया के राष्ट्रपति
वासुदेव कुटुंबकम!
अह, क्या?...

इलाके की सुरक्षा के लिए भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं।
पीछे हटो! गेट पर आने की इजाज़त नहीं है!
अरे वाह! हम क्यों हटें? इतनी दूर से हटने के लिए आए हैं?
हटना तो उन्हें चाहिए जो हमारा खून चूसते हैं, जिनकी सुरक्षा में तुम खड़े हो।
जी-20 मुर्दाबाद!
इसी बीच, गेट पर विरोधियों की भारी भीड़ जमा हो गई है।
G20 GO BACK
G POVERTY PEOPLE
2 POLLUTION PLANET
0 PARALYSIS PROSPERITY

ज़ाहिर सी बात है, शक्तिशालियों के सम्मेलन की शुरुआत एक भव्य भाषण से ही होगी।
मेरे दोस्तों! हम विश्व की प्राचीनतम सभ्यता हैं। तो यह उचित ही है कि इस बार जी-20 की मेज़बानी हम कर रहे हैं। भारत सभी देशों में प्रगति का एक स्वर्णिम प्रतीक बन गया है...
सुनो तो इसे! कैसे गुब्बारे की तरह फूल रहा है। इसके देश ने सभ्यता तो हमारे लोगों से सीखी है।
चों – चों
चों – चों
चों – चों
अपनी तूती बजाने दो। देखना, बाद में गुब्बारा फटने पर खूब मज़ा आएगा!
फ्रांस के प्रधाम मंत्री
ही ही ही ही
चीन के राष्ट्रपति
उम्मीद है आपके नए परमाणु प्लांट अच्छे से निर्माण किए जा रहे हैं। हमने तो पहले से ही चार नई युरेनीअम खानों पर काम शुरू कर दिया है।
हम कर रहे हैं, पर हमारे देशवासी बात का बतंगड़ बनाने की बातें ढूंढते रहते हैं!
इतना ज़रूर कहूँगा कि आप ऐसी मुश्किलों से बेहद अच्छी तरह जूझते हैं!
हा हा हा ...
बिल्कुल! हम आवाज़ दबाने की तकनीकों पर खासा ध्यान देते हैं!

सभी नेतागण एकत्रित हो कर मुस्कुराहटों के ज़रिए अपना सौहार्द और सद्भावना प्रकट करते हैं।
मुझे उसके साथ खड़े हो कर मुस्कराने के लिए एक और पेग पीना पड़ेगा!
ही ही, यह मोर तो अमरीका और इसराईल से घनी मित्रता जता रहा है।
मानना पड़ेगा, दाँत तो नहीं हैं मोर के, पर पंख खूब फड़फड़ाता है!
रूस के प्रधान मंत्री
ब्राज़ील के प्रधान मंत्री
CLICK
CLICK
इस बीच, बाहर भीड़ एक युवा लड़की के चारों ओर घेरा बनाती है।
दोस्तों, मैं यहाँ कोसों दूर से आई हूँ।
हम महाराष्ट्र में कपास की खेती करते हैं और अब अपनी जीविका के लिए लड़ रहे हैं।

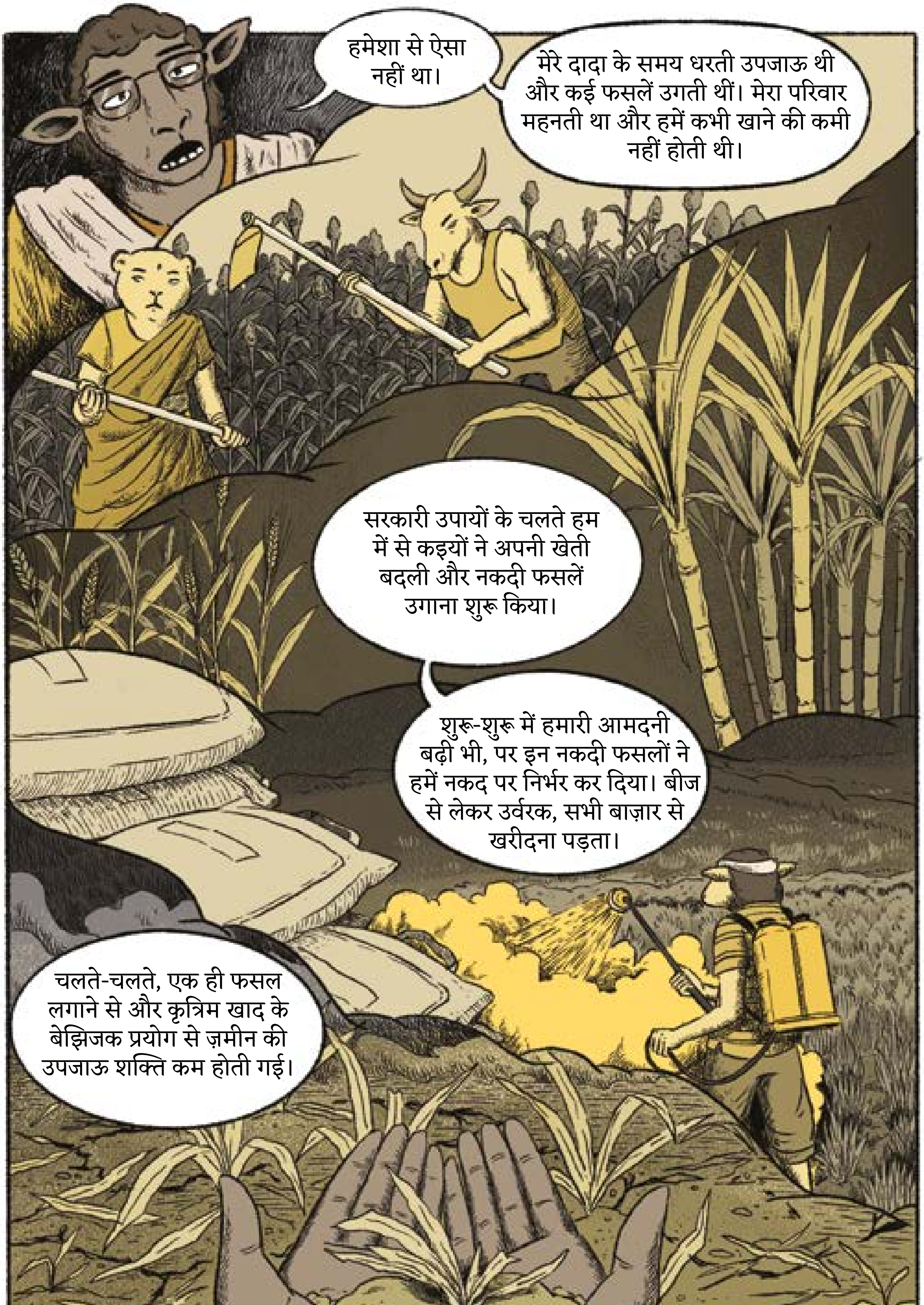
हमेशा से ऐसा नहीं था।
मेरे दादा के समय धरती उपजाऊ थी और कई फसलें उगती थीं। मेरा परिवार महनती था और हमें कभी खाने की कमी नहीं होती थी।
सरकारी उपायों के चलते हम में से कइयों ने अपनी खेती बदली और नकदी फसलें उगाना शुरू किया।
शुरू-शुरू में हमारी आमदनी बढ़ी भी, पर इन नकदी फसलों ने हमें नकद पर निर्भर कर दिया। बीज से लेकर उर्वरक, सभी बाज़ार से खरीदना पड़ता।
चलते-चलते, एक ही फसल लगाने से और कृत्रिम खाद के बेझिजक प्रयोग से ज़मीन की उपजाऊ शक्ति कम होती गई।

हम मानो एक भंवर में फस गए। हमारी उधारी बढ़ती गई और पैदावार घटती गई।
कई तो अपना उधार चुका नहीं पाए। कुछ ने अपनी ज़मीन बेची और काम ढूंढते शहर को आए।
जो गाँव मे रह गए, कर्ज़ में डूबते गए। मजबूरी में कईयों ने आत्महत्या कर ली।
इस साल तो फसल की कीमत इतनी गिर गई है कि मुनाफा तो दूर, हम अपना सालाना कर्ज़ भी नहीं चुका पाएंगे!
छोटे किसानों का यह हाल है तो भूमिहीन किसान और बटईदार का आप सोच ही सकते हैं।

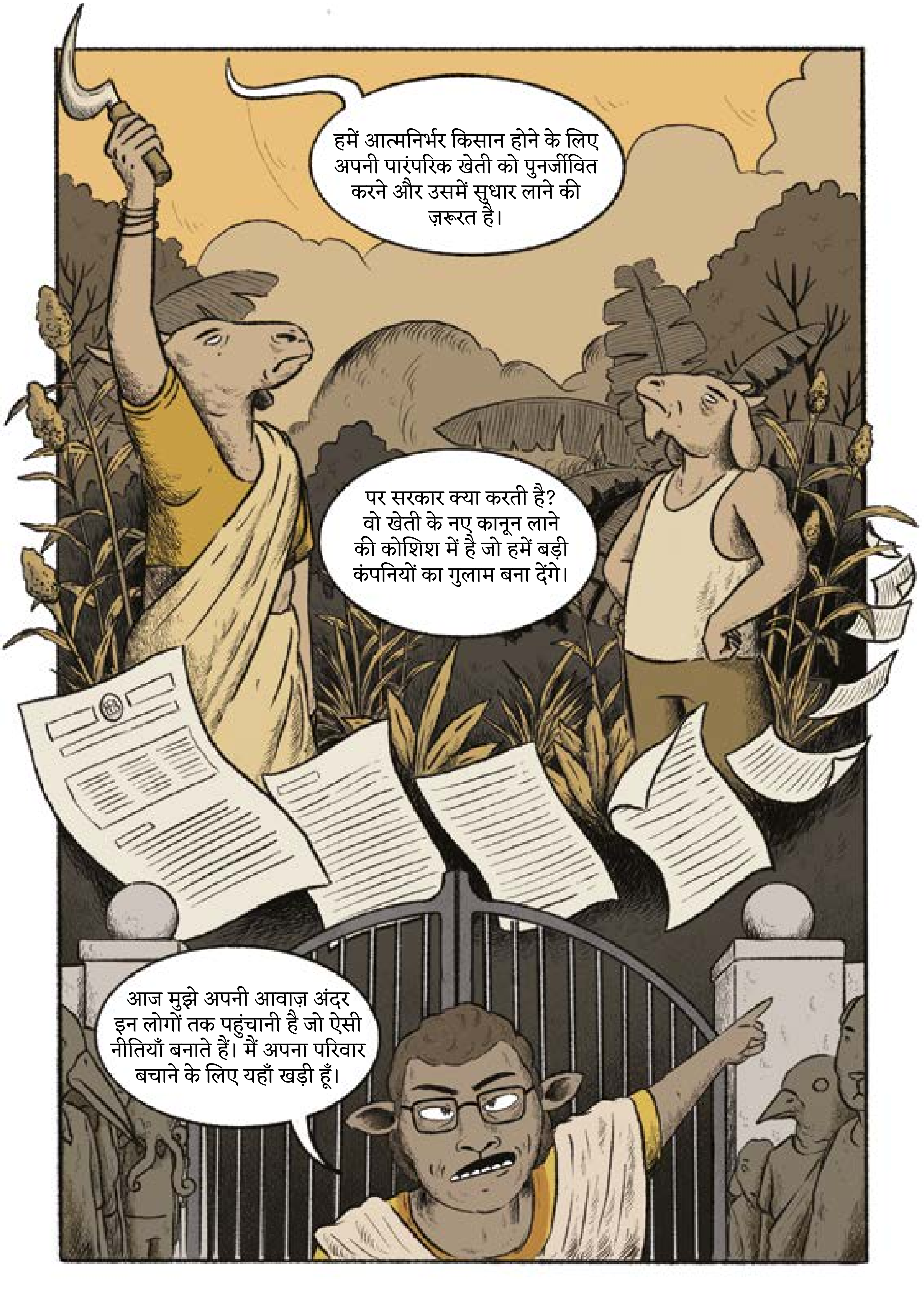
हमें आत्मनिर्भर किसान होने के लिए अपनी पारंपरिक खेती को पुनर्जीवित करने और उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है।
पर सरकार क्या करती है? वो खेती के नए कानून लाने की कोशिश में है जो हमें बड़ी कंपनियों का गुलाम बना देंगे।
आज मुझे अपनी आवाज़ अंदर इन लोगों तक पहुंचानी है जो ऐसी नीतियाँ बनाते हैं। मैं अपना परिवार बचाने के लिए यहाँ खड़ी हूँ।

भूख!!!
आप में से कितने जानते हैं कि असली भूख क्या है और उससे लोगों पर क्या बीतती है?
लेकिन अंदर का माजरा कुछ और ही है...
हमारी नीतियों को दुनिया के लाखों भूखे लोगों की आहार सुरक्षा के लिए एक मानवीय और सैद्धांतिक दृष्टिकोण पर आधारित होने की आवश्यकता है।
भई वाह!
क्या बात है!
अमरीका के राष्ट्रपति
लेकिन...
स्थिर बाजारों के बिना यह कैसे संभव है? खाद्य उत्पादन तो तभी बढ़ेगा जब अर्थव्यवस्था आश्वस्त हो!
खाद्य सुरक्षा की नींव केवल हमारी ज़बरदस्त निजी कंपनियां रख सकती हैं!
माफ़ करिए जनाब!

छोटे किसान तो इन मुनाफाखोर कंपनियों के द्वारा कुचल दिए जाएंगे।
हाँ! जब हमारे किसान ही भूखे हों तो हम आत्मनिर्भर कैसे हो सकते हैं?
क्या खाद्य सुरक्षा सरकारों की जिम्मेवारी नहीं है?
कृषि सचिव, केन्या
सरकार की जिम्मेवारी बताते हो? तुमने ही अपने लोगों को मिट्टी में मिलाया है अपनी संरक्षणवादी विचारधारा से!
जागिए और अपने बाजार खोलिए मैडम! बाजार के तंत्र सब कुछ संभाल सकते हैं! सब कुछ!
सब कुछ!
हा हा हा हा
SPLASH
SPONSORED BY MEGACORP®
जो आप कह रहे हैं वो किसानों के अधिकारों पर यूनाइटेड नेशन्स की अंतर्राष्ट्रीय संधि के खिलाफ है!

प्रधान मंत्री
यूनाइटेड किंगडम
हा हा हा हा
यूनाइटेड नेशन्स? ज़रा अपने चारों ओर नजर घुमाइए मंत्री महोदय! यूनाइटेड नेशन्स तो हम ही हैं!
ताकतवर देश अपने छल प्रयोजनों में लगे हैं और इतने में बाहर लोग अपनी सचाइयों से जूझ रहे हैं।
बच्चे भूखे हैं। रसोई का इंतज़ाम करना चाहिए...
SAVE CLIMATE REFUGEES

भाइयों और बहनों, आपको विश्वास नहीं होगा, पर हमने अपनी आँखों से देखा है!
SAVE CLIMATE REFUGEES
समुद्र देवता, जो हमारा अन्नदाता है, और सदियों से हमारा पोषण करता आया है, अब नाराज़ है।
हम मछुआरे हैं, हमारा पेट वही भरता है। हमें पहले ही संकेतों पर ध्यान देना चाहिए था।
पिछले कुछ सालों से दरिया हमारे घरों की तरफ बढ़ रहा था पर इस साल तो वो उनको पूरा निगल गया।
गाँव में कुछ नहीं बचा। सिर्फ मलवा। जाने को कोई जगह नहीं है।

यहाँ कोई भी ढांचा बनाना गैर-कानूनी है। हटाओ इनको! निकलो यहाँ से!
हमारे बच्चों को एक खुशहाल भविष्य का हक नहीं है क्या?
क्या हम अपने ही देश से भीख मांगे हमें स्वीकारने के लिए?
हमारी बदहाली के लिए हम हीं ज़िम्मेदार हैं क्या?
CRASH
DHUD
DHUD
गाँव के गाँव डूब रहे हैं, और विश्व के महान देशों के नेता अपने ही भ्रम में डूब रहे हैं।

और अब हरित भविष्य के लिए एक टोस्ट!
हम महान देशों के लीडरों ने बड़े-बड़े कदम उठाए हैं जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए। इसके लिए मैं आप सभी को सलाम करता हूँ।
प्रधान मंत्री, ऑस्ट्रेलिया
पर हमें याद रखना होगा कि अभी युद्ध बाकी है ...
यह देखते हुए कि पूरी दुनिया अब भी तेल, कोयला और गैस पर निर्भर है, हम किसी जादुई छड़ी से उनकी खपत तो नहीं रोक सकते।
तो आगे का रास्ता क्या है?
हमें छोटे और निर्धारित कदम उठाने होंगे।
मिसाल के तौर पर, मेरे मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत दारू-निर्भरता-घटौती-योजना को ही ले लीजिए।

हमने उद्योगपतियों को आश्वस्त किया है कि इससे लघु और मध्य काल में उनके पीने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब हमें उनका पूरा समर्थन है!
ज़रा सोचिए, हम दारू से गैर-मादक पेय पर रातों रात थोड़ी परिवर्तित हो सकते हैं। लंबे समय के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए, लघु काल में बीयर उपभोगता बढ़ाने में निवेश तो करना पड़ेगा।
मेरा मंत्रिमंडल, जो उदाहरण से नेतृत्व करता है, और जो औसतन 73 साल का है, इसलिए अब 100 साल की आयु तक सामान्य तरीके से दारू पिएगा।
उसके बाद वे दारू पीना कम करेंगे जिस से कि दस साल के अंदर नेट ज़ीरो दारू की खपत करेंगे।
दारू का उपभोग जल्द से जल्द 2060 तक खतम हो सकता है!

अगर ऐसी बात है तो हमारे लिए 20 साल और जोड़ दीजिए! आखिर हम विकासशील देश हैं!

क्या दूरदर्शिता है, मंत्रीजी!
एक जाम भविष्य के नाम!

सर!!
Bzzz
Bzzz
Bzzz
Bzz
विरोध प्रदर्शन?! शरणार्थी! ज़रूर यह सम्प्रदायवादी षड्यन्त्र है!
सर, प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जलवायु संकट पर तुरंत कदम उठाए जाएं। उन्होंने तो भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है।
देखो, हर तरफ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तैनात है, और हम यहाँ नेटवर्क को निलंबित भी नहीं कर सकते।
स्तिथि काफी खराब है, सर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सख्त कार्यवाही करने की इजाज़त मांगी है।
मुझे सोचने दो...

इसरेली
प्रधान मंत्री
PAT PAT
उनसे कहो कि तुरंत प्रदर्शन के लीडरों को UAPA के तहत गिरफ्तार करें। बाकी मैं संभाल लूँगा। हमें अपने दोस्तों का सहयोग है।
वैसे भी, उपद्रवियों को तो उनके कपड़ों से ही पहचाना जा सकता है, समझे ना?
गेट की दूसरी ओर सभी जन्तु लंबी लड़ाई के लिए जुट गए हैं।

AISE DASTOOR KO, SUBA
MAIN NAHI MANTA! MA
सहेंगे!
जगह जगह से जीव आकर प्रदर्शन से जुड़ते जा रहे हैं – विद्यार्थी, शिक्षक, किसान, मज़दूर ...
जी-20 मुर्दाबाद!
जी-20 मुर्दाबाद!
AZADI!
UNITE! against IMPERIALISM
अत्याचार नहीं सहेंगे!
WE SHALL FIGHT! WE SHALL
G20 Go Back
यह लड़ाई चंद लोगों की नहीं, यह हम सब की जंग है!
हमारी लोकतान्त्रिक संस्थाएँ बेड़ियों में कैद हैं, हमारी आवाज़ों पर इनकी गोदी मीडिया ने ताले लगा दिए हैं!
हम सब मिल कर भुगत रहे हैं तो हमें मिल कर ही लड़ना पड़ेगा। हम सभी, जो जी-20 देशों की अत्याचारी नीतियाँ, पुलिस राज्य, सैन्य अजेंडा से संघर्ष कर रहे हैं ...
जनशक्ति ज़िन्दाबाद!

...हम इस भूमि के सभी वंचित और उत्पीड़ित प्राणियों के ऐतिहासिक संघर्षों के साथ खड़े हैं।
वे हमें राष्ट्रविरोधी कहते हैं पर देश प्रेम क्या होता है उन्हें इसकी समझ है?
WEEEUUUUUUWEEEUUUUW
WEEEUUUUUU
हमें अपने संघर्ष जोड़ने होंगे – विद्यार्थी, रेफ्यूजी, मज़दूर, किसान... एकता!
इंक़लाब ज़िन्दाबाद!

मित्रों, हम यहाँ एकत्रित हुए हैं जिससे सम्पूर्ण विश्व में शांति और स्थिरता लंबे समय तक स्थापित हो सके।
पर कुछ लोग हैं जो हमारी सफलता से जलते हैं। वे दुष्ट लोग दुनिया भर में कहर और असामंजस्य फैलाना चाहते हैं।
आज ही, हमारी चौकन्नी पुलिस ने हमारी सभा पर ऐसे एक हमले को नाकाम किया!
इन देशद्रोहियों ने देश के गौरव और कड़ी मेहनत से मिली वैश्विक मान्यता को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की!
ओह!
ओह!
ओह!
पर ऐसे प्रयास कभी सफल नहीं हो पाएंगे। क्यूंकि इनसे हमारे देश को सुरक्षित रखने का संकल्प और द्रढ़ होता है।

WHERE ARE THESE TERRORISTS?
All those detained are students, Refugees & Farmers!
लोकतंत्र के सभी स्तम्भ जनता के हित में कार्यरत हैं।
हमारा न्यायतंत्र, विधायक मंडल, कार्यपालक और मीडिया दूसरे देशों की ईर्ष्या के पात्र हैं।
WORLD LEADERS PRAISE INDIA!
हमारा मानवधिकार रिकार्ड तो अद्वितीय है।
ANTINATIONAL THREAT AT G20
धर्मनिरपेक्षता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमारी सफलता का एक अहम पहलू है।
हमें लोगों का पूरा समर्थन प्राप्त है। हम सभी मिल कर विकास की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं!
जी-20 सम्मेलन समाप्त होते ही लोगों का खून-पसीना सड़कों से धो दिया जाता है और जगह फिर से चमकने लगती है।
G20

विश्वास नहीं होता!
क्या हुआ फातिमा?
ATTEMPTED DISRUPTION AT G20
BHARAT TIMES
G20 SUMMIT A SUCCESS!
जी-20 सम्मेलन ने फिर से हमारे साथ धोका किया है।
ढोंगी कहते हैं कि बहुत कुछ हासिल कर लिया है पर कोई सही कदम नहीं उठाया गया है।
मुझे तो इस से ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी। हर साल ऐसा ही तो होता है!
अम्मी साल-दर-साल ऐसे नहीं चल सकता!
हमारा भविष्य इन क्रूर पूंजीवादियों और जंगबाज़ों के हाथों में है जो अपने स्वार्थ के आगे कुछ नहीं देखते।
हमारे ही प्रधान मंत्री ने 2070 की सीमा निर्धारित करी है नेट ज़ीरो एमिशन के लिए! सब को मालूम है कि इससे किसको फ़ायदा होगा और किसको कीमत चुकानी पड़ेगी!

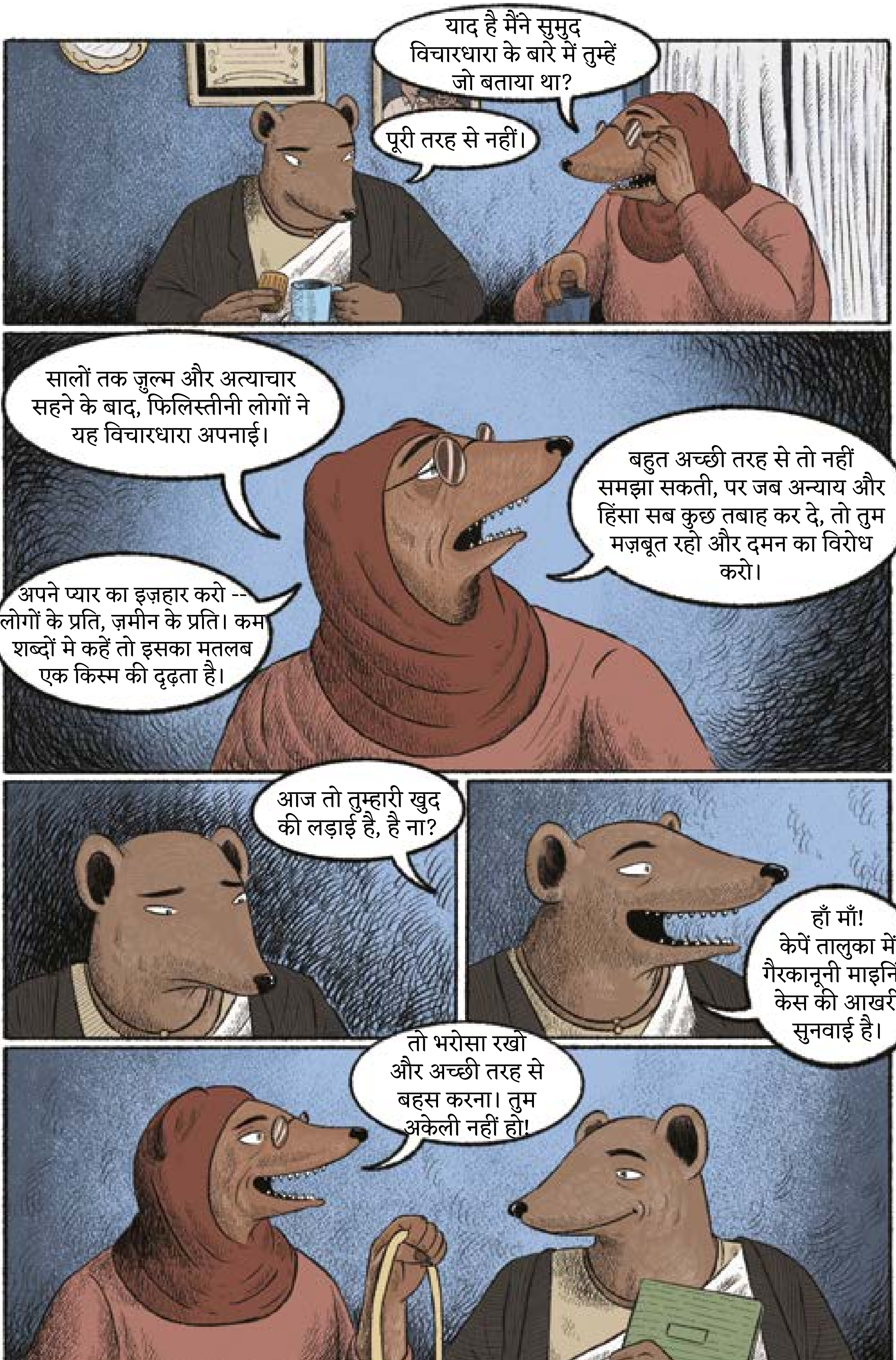
याद है मैंने सुमुद विचारधारा के बारे में तुम्हें जो बताया था?
पूरी तरह से नहीं।
सालों तक ज़ुल्म और अत्याचार सहने के बाद, फिलिस्तीनी लोगों ने यह विचारधारा अपनाई।
बहुत अच्छी तरह से तो नहीं समझा सकती, पर जब अन्याय और हिंसा सब कुछ तबाह कर दे, तो तुम मज़बूत रहो और दमन का विरोध करो।
अपने प्यार का इज़हार करो -- लोगों के प्रति, ज़मीन के प्रति। कम शब्दों मे कहें तो इसका मतलब एक किस्म की दृढ़ता है।
आज तो तुम्हारी खुद की लड़ाई है, है ना?
हाँ माँ! केपें तालुका में गैरकानूनी माइनिंग केस की आखरी सुनवाई है।
तो भरोसा रखो और अच्छी तरह से बहस करना। तुम अकेली नहीं हो!

मैं इन लड़ाइयों में अपने को कभी अकेला नहीं पाती, माँ। इस जंग में सबसे आगे छात्र और नौजवान हैं जो अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। मैं तो केवल उन्हें अदालत में मदद करती हूँ!
STOP ILLEGAL MINING!

और हम जीतेंगे, हर संग्राम को!

ग्रूप ऑफ ट्वेंटी की शुरुआत

जी-20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के मद्देनजर हुई थी। जी-7 (ग्रुप ऑफ सेवन) के वित्त मंत्रियों द्वारा वित्तीय और आर्थिक प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए इस मंच की घोषणा की गई थी। यह दुनिया की बीस सबसे बड़ी स्थापित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकरों को एकजुट करने का माध्यम बनी। हालाँकि राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के स्तर पर जी-20 बैठकें उच्चतम राजनीतिक स्तर पर पूंजीवाद को बचाने के लिए संकट समन्वय के एक तंत्र के रूप में 2008 के वित्तीय संकट के कारण अस्तित्व में हैं। तब से जी-20 नेताओं ने नियमित रूप से मुलाकात की है, और जी-20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए केंद्रीय मंच बन गया है। जी-20 अर्थव्यवस्थाएं क्रय शक्ति समता (purchasing power parity) के लिए समायोजित सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के संदर्भ में वैश्विक आर्थिक उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत उत्पादन करती हैं और सामूहिक रूप से वैश्विक व्यापार का तीन-चौथाई हिस्सा हैं। दुनिया भर में निर्यात की सबसे बड़ी मात्रा वाले 20 देशों में से 15 जी-20 के सदस्य हैं। और दुनिया की दो-तिहाई आबादी जी-20 के सदस्य देशों में बसती है।

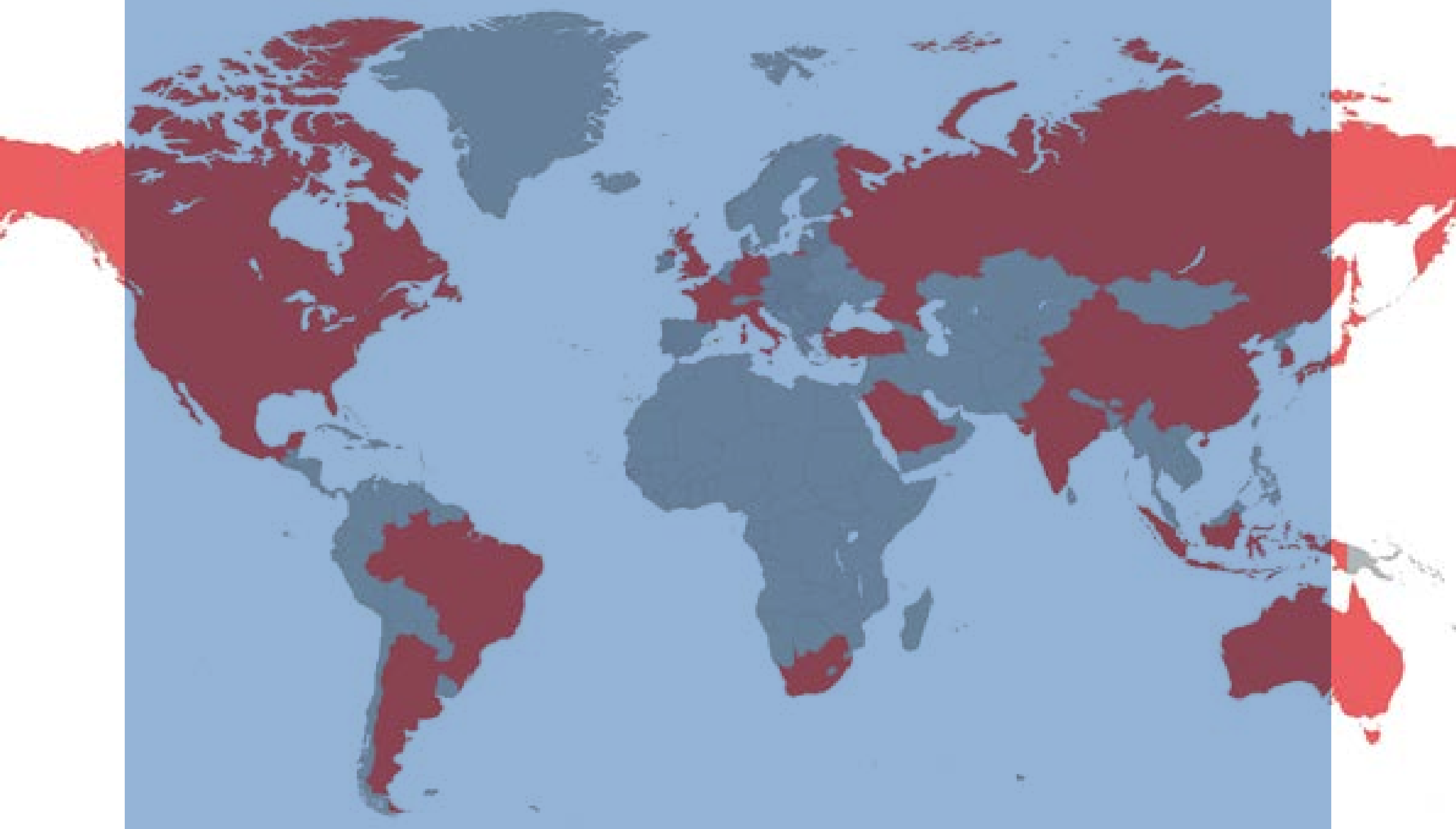

एक चुनिंदा मंच: रचनात्मक तौर से विशेष और सुविधाजनक

जी-20 की सदस्यता, या यूँ कहें, जी-7 (और बाद में जी-8) से जी-20 का विस्तार एक स्वयंभू कॉलेजियम की ओर इशारा करता है जो एक इच्छा से उभरा -- वैश्विक आर्थिक प्रणाली के एक बड़े पुनर्गठन के बिना एक साम्राज्यवादी जड़ को कायम रखने की इच्छा।

सीधे शब्दों में कहें तो जी-20 की संरचना एक योजना है जिसका उद्देश्य है मुट्ठी भर विकासशील देशों के सांकेतिक प्रतिनिधित्व से वैधता हासिल करना।

कुछ देशों को दूसरों के बजाय इसमें शामिल करने का निर्णय बहुत सारे प्रश्न खड़े करता है।

रूस और चीन का समावेश तो इसमें होना ही था और इसके लिए आह्वान भी किया गया था। लेकिन ईरान के बजाय सऊदी अरब को शामिल करना; मिस्र और नाइजीरिया के ऊपर दक्षिण अफ्रीका (इसके बावजूद कि वे अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं); और वेनेजुएला के बजाय मेक्सिको, अर्जेंटीना व ब्राजील को शामिल करना, यह सभी इसकी सदस्यता पर प्रतिबंधों के कुछ उल्लेखनीय उदाहरण हैं।

उस समय उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समावेश, जी-7 का बहुपक्षीय संस्थानों पर नियंत्रण करने का, और विकासशील दुनिया में उभरते खिलाड़ियों से व्यापक वैधता और समर्थन हासिल करने का एक संक्षिप्त मार्ग था।

कहना गलत नहीं होगा कि यह ग्रूप अपने आप में आर्थिक न्याय की कहानी गढ़ने से बहुत दूर है, क्योंकि इसने 'ब्रेटन वुड्स' संस्थानों के अधिक पुनर्गठन के बिना ही वैश्विक पूंजीवाद का प्रबंधन करने का बीड़ा उठाया है।

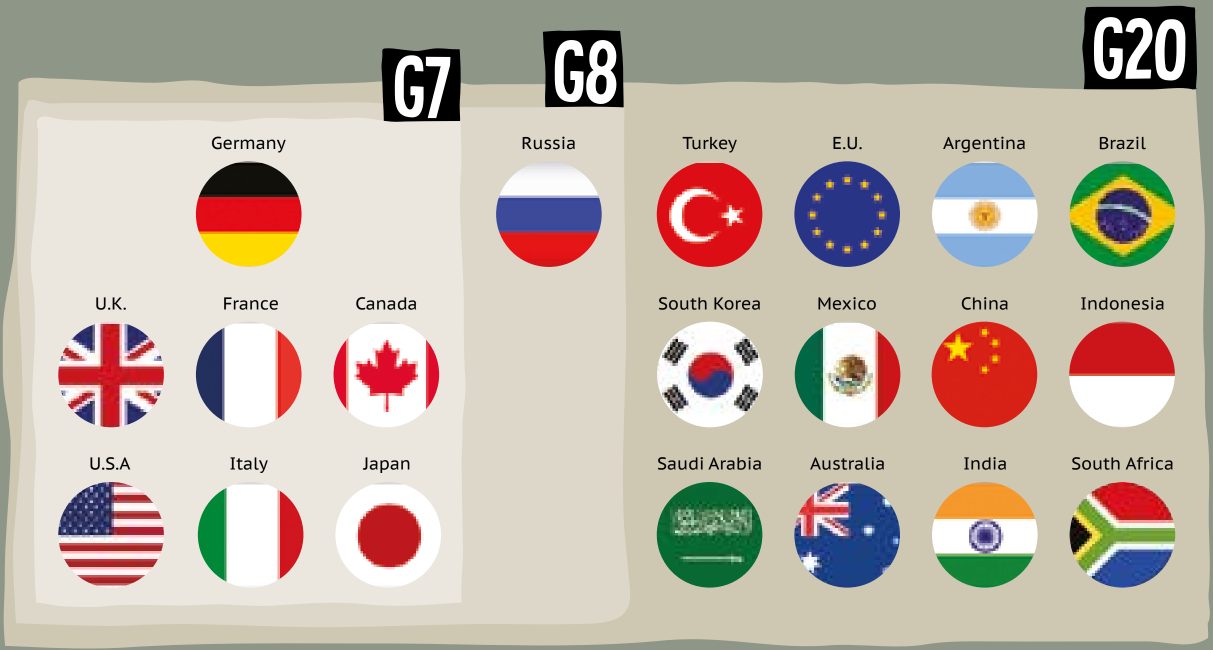

जी-20 कैसे काम करता है?

जी-20 कोई स्थायी संस्था नहीं है जिसका कोई मुख्यालय, कार्यालय, सचिवालय या कर्मचारी हों। इसका एजेंडा और गतिविधियां सभी सदस्य देशों के परामर्श से, 'रोटेटिंग प्रेसीडेंसी' द्वारा तय की जाती हैं। निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, 'ट्रोइका' की व्यवस्था लागू है। ट्रोइका में वर्तमान मेजबान देश, उसके पूर्ववर्ती और उसके उत्तराधिकारी शामिल रहते हैं। 2023 की अध्यक्षता भारत द्वारा की जाएगी।

जी-20 बैठकें तीन प्रमुख धाराओं में होती हैं। 'वित्त ट्रैक', जहां प्राथमिक ध्यान वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर है, जैसे कि मौद्रिक, राजकोषीय और विनिमय दर नीतियाँ, बुनियादी ढांचे में निवेश, वित्तीय विनियमन, वित्तीय समावेशन, और अंतरराष्ट्रीय कराधान, इत्यादि। इस ट्रैक में, इन देशों की सरकारें (अपने वित्त मंत्रियों के माध्यम से) और केंद्रीय बैंक के गवर्नर साल भर मंत्रिस्तरीय बैठक करते हैं। मंत्रिस्तरीय बैठकों के परिणामों को वार्षिक जी-20 शिखर सम्मेलन में संकलित किया जाता है, जहाँ नेता निष्कर्षों के आधार पर अपने निर्णय तैयार और लागू करते हैं और एक विज्ञप्ति निकालते हैं।

'शेरपा ट्रैक' महत्वपूर्ण व्यापक मुद्दों पर केंद्रित है, जिसमें प्रमुख मुद्दे, जैसे राजनीतिक जुड़ाव, लैंगिक समानता, व्यापार, सतत विकास, ऋण, आदि हैं। साथ में महामारी, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, प्रवासन जैसे विरसतीय और प्राथमिक एजेंडा भी शामिल हैं। देश अपने-अपने दूतों और मंत्रालयों के ज़रिए इन बैठकों में भाग लेते हैं। जी-20 सदस्य राष्ट्रों ने विभिन्न 'सिवल सोसाइटी' या सामाजिक स्टेक्होल्डर से व्यापक भागीदारी प्राप्त करने के लिए 'एंगेजमेन्ट ग्रूप' (वर्तमान में कुल 8) भी बनाए हैं। उन्हें सरकार का प्रतिनिधित्व करने के बजाय स्वायत्त, स्वतंत्र समूहों के रूप में काम करने का अधिदेश है।

जी-20 की मुख्य भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव डालना, संवाद को सुविधाजनक बनाना, और विशेष रूप से वर्तमान अन्योन्याश्रित बाजार अर्थव्यवस्थाओं और वैश्विक पूंजीवाद के रखरखाव के लिए संतुलन को संस्थागत बनाना। वैश्विक शासन के मौजूदा ढांचे में जी-20 को एक अनौपचारिक मानदंड निर्माता के रूप में देखा जा सकता है, जहां अधिकांश नीति सिफारिशें 'क्लब गवर्नेंस' प्रारूप से निकलती हैं। बाद में, यह 'क्लब गवर्नेंस' प्रारूप वैश्विक वित्तीय वास्तुकला में प्रभावशाली हो गया है और विरोधों का एक प्रमुख स्थल बन चुका है ।

जी-20 के कुछ आसन्न मुद्दे

पहले,
जी-20 एक संयुक्त सुसंगत संस्था नहीं है और आंतरिक और संरचनागत विभाजनों से ग्रस्त है। यह जी-7 की तुलना में अधिक लोकतांत्रिक प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी यह एक स्व-नियुक्त 'ऐलीट' निकाय को 'टॉप-डाउन' तरीके से कार्य करने का प्रतिबिंब है क्योंकि वे वैश्विक आर्थिक उत्पादन का 80% हिस्सा बनाते हैं। इससे यह सवाल उठता है कि जब वैश्विक दक्षिण के कुछ प्रमुख देश अनुपस्थित हैं, तो किस प्रकार के मैक्रोइकॉनॉमिक समन्वय की मांग की जा रही है, या कभी आर्थिक न्याय फ्रेम में था भी?

दूसरे,
अपनी तरह के कई समूहों की तरह, जी-20 का अपना एक इतिहास है। अपनी किशोरावस्था में क्लब ने आर्थिक नीति के फ्रेम से परे जाने वाले मुद्दों पर चर्चा करना शुरू कर दिया, जिससे इसे एक अंतर-सरकारी राजनीतिक मंच के तौर पर एक नया रूप दिया गया है। हालांकि, अन्य राजनीतिक मंचों की तरह, यह किसी भी महत्वपूर्ण एजेंडा पर ठोस उपाय देने के बजाय केवल एक 'हाई-प्रोफाइल टॉकिंग शॉप' होने का दावा करने में कामयाब रहा है। जलवायु परिवर्तन, न्यायपूर्ण ऊर्जा संक्रमण, न्यायसंगत व्यापार, और तीसरी दुनिया के ऋण, सभी ऐसे मुद्दे हैं जो ध्यान तो आकर्षित करते हैं लेकिन उनमें या तो कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठ पाते या फिर अंत में 'निओ-लिबरल' नीति के नुस्खे लागू कर दिए जाते हैं।

तीसरा,
जी-20 आर्थिक शासन के लोकतंत्रीकरण के रास्ते में एक बड़ी बाधा है। कई तरह से यह उन शक्ति विषमताओं और राजनीतिक अर्थव्यवस्थाओं से गहरी तरह घुला मिला है जो वर्तमान में वैश्विक श्रम विभाजन पर हावी हैं। ये उन संस्थानों के भी प्रतीक हैं जो श्रम के उस विभाजन को बढ़ावा देते हैं और दुनिया की घिसी पिटी निओ-लिबरल (नवउदारवादी) विचारधाराओं के प्रतीक हैं। जी-20 का गठन संयुक्त राष्ट्र के तहत समान स्तर के समन्वय स्थापित करने के प्रयास को कमजोर करने का था। लेकिन जी-20 ने एक ऐसी प्रक्रिया कायम की जो आर्थिक शासन की संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रियाओं के साथ मेल खाती है और कभी-कभी खुद को भी बाधित करती है।

भारत और 2023 जी-20 प्रेसीडेंसी: भारतीय सिविल सोसाइटी के लिए चुनौतियां

यह पूछना महत्वपूर्ण है कि इस मंच में भारत की क्या भूमिका रहेगी। क्या यह कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को चर्चा के लिए मेज़ पर ला पाएगा? या फिर यह केवल जी-7 प्रक्रियाओं में लिए गए निर्णयों को वैध बनाने में मदद करेगा। यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि तीसरी दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को कैसे तैयार किया जाता है और क्या शिखर सम्मेलन स्वयं अस्पष्ट वादों से समाप्त होता है, जहाँ कोई स्वतंत्र विचार ना पेश कर, विकसित दुनिया के साथ ही चलने की मंशा है? इस स्थिति में नागरिक समाज की भूमिका इन मुद्दों को देखने और संबोधित करने के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है । साथ ही, यह मान लेना भी गलत होगा कि इस संदर्भ में दक्षिणी (वैश्विक दक्षिण) नेतृत्व अनिवार्य रूप से प्रगतिशील होगा क्योंकि 'ग्लोबल साउथ' में बहुत सी सरकारों ने 'निओ-लिबरलिस्म' को अपनाया है और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पूंजी का हिस्सा हैं। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में असमानता के आंकड़ों को देखते हुए इन्हें आसानी से 'ग्लोबल ऐलीट' का हिस्सेदार समझा जा सकता है।

जबकि आधिकारिक शिखर सम्मेलन में मौजूदा गड़बड़ी, निर्बलता और निष्क्रियता कायम रह सकती है और नेताओं की कल्पना और वचनबद्धता में कमी दिख सकती है, स्पष्ट रूप से, कार्य रहेगा टूटी व्यवस्था को जोड़ना और कार्रवाई के लिए समयसीमा तय करना। हालाँकि, हम कई मोर्चों पर अकल्पनीय पैमाने के संकट के करीब हैं और यह स्थिति न तो वांछनीय है और न ही टिकाऊ। इनमें से कुछ संस्थानों के खिलाफ बौद्धिक संघर्ष के स्तर को बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि जब वैश्वीकरण की ताकतें राष्ट्रीय अंतरिक्ष में प्रवेश करती हैं तो उनके साथ आने वाली नियामक शक्ति का विरोध करना कठिन हो जाता है।

भारतीय सिविल सोसाइटी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि 2023 शिखर सम्मेलन से पहले होने वाले विचार-विमर्श समावेशी हों और राष्ट्रीय भौतिक संदर्भों पर आधारित हों और साथ ही में एक अंतर्राष्ट्रीयवादी दृष्टिकोण रखें ताकि हम अपनी उप-साम्राज्यवादी स्थिति से अलग हो सकें। प्रयास होना चाहिए कि निर्माण नीचे से और सीमाओं से परे हो।

‘चाय-पानी’ झील के किनारे एक विशाल स्थल बनाया गया है जो सर्वश्रेष्ठ सुविधाओं से सुसज्जित है और जहाँ दुनिया के नेता व अंतर्राष्ट्रीय प्रेस जी-20 (गैंग ऑफ 20) की वार्षिक बैठक की भव्यता और गरुर देखने के लिए जमा हुए हैं। देश भर से आए जंतुओं के बीच गैंग ऑफ 20 द्वारा दिखाए गए कल्पना, प्रतिबद्धता और कार्रवाई की कमी को ले कर तनाव है। आयोजन स्थल के अंदर भ्रामिक खेल जारी है जबकि जनता नई वास्तविकता का सामना कर रही है। ‘इंकलाब जिंदाबाद’ के नारे गूँजते हैं और सर्वोच्च नेता को इन ‘राष्ट्र विरोधी’ तत्वों की सूचना दी जा चुकी है। पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर चुकी है, लेकिन इस बार बात कुछ अलग है - किसान, मजदूर, छात्र, रेफ्यूजी और हाशिए पर पड़े लोग एकजुट हैं। तैयार एक जंग के लिए।

मुनाफाखोरों, ताकतवर, और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को अपने बैंक विवरण की चकाचौंध डिजिटल रोशनी, उसमें तैरते पैसे, और दूसरों से चुराई सामाजिक संपत्ति के अलावा और कुछ नहीं दिखता। यह सामयिक कॉमिक हमें विश्व नेतृत्व की कठोर नीरसता की एक झलक देती है। यह बताती है कि हमें कुछ बेहतर चाहिए। ऑक्सीजन, शायद, वातानुकूलित शून्य की बासी हवा के बजाय।

- विजय प्रशाद

बड़ी सटीकता से यह कॉमिक शक्ति के अहंकार को, और प्रतिरोध की अनिवार्यता को उजागर करती है। यह व्यंग्य की भी एक उच्चतम मिसाल है।

- नीरा चंदोक

CFA